International Journal of Applied Research 2016; 2(2): 818-819

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(2): 818-819
www.allresearchjournal.com
Received: 02-12-2016
Accepted: 05-01-2016

डॉ0 मो0 शाहिद अख्तर
+2 मुकुन्दी चौधरी हाई स्कूल,
कादिराबाद, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 मो0 शाहिद अख्तर
+2 मुकुन्दी चौधरी हाई स्कूल,
कादिराबाद, दरभंगा, बिहार, भारत

उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति

डॉ0 मो0 शाहिद अख्तर

सारांशः
भारत में, उदारीकरण को औद्योगिक संवृद्धि और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को गतिमान करने के उद्देश्य से अपनाया गया था, उदारीकरण के तहत भारतीय और विदेशी उद्यमी ऊर्जा, परिवहन, संचार, पेट्रोलियम जैसे कई क्षेत्रों में प्रवेश किए, नवीन औद्योगिक नीति को नौकरशाही की भूमिका को कम करने के लिए अपनाया गया। उदारीकरण के अधिकतर उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म किया। उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप देश में उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बेहद वृद्धि हुई, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में मंदी पर लगाम लगाई, सफल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, उदारीकरण से अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी व्यापक बदलाव आया तथा एक देश की अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाने लगा। उदारीकरण के दौर में सम्पूर्ण विश्व की विदेश नीति सी लगातार बदल रही है। प्रत्येक देश एक दूसरे देश से अपसे संबंध मजबूत और मधुर बनाने का प्रयास कर रहा है।

प्रस्तावनाः
आजादी के बाद जहाँ भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी वहीं कई आंतरिक चुनौतियाँ भी मौजूद थीं। तो दूसरी तरफ शीत युद्धकालीन वैश्विक व्यवस्था की मौजूदगी, ऐसे में दोनों चुनौतियाँ से निपटना भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौति थी। इसलिए भारत ने बीच का रास्ता चुना और गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। इसके साथ ही, शांति की स्थापना और भारत द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पंचशील सिद्धांत का भी योगदान महत्त्वपूर्ण है। इस दौर में विदेश नीति का निर्धारण सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता रहा।
1991 के उपरांत द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की समाप्ति के बाद वैश्विक समुदाय आर्थिक सुधारों की ओर अग्रसर हुए। इस संदर्भ में भारत ने भी अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्त्तन कर उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया और आर्थिक विकास पर बल दिया जिसमें भारत को सभी महत्त्वपूर्ण देशों के साथ संबंध सुधारने का अवसर प्रदान किया। इस तरह विदेश नीति आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होने लगी। वैश्वीकरण द्वारा सृजित आत्म निर्भरता के कारण दो और दो से अधिक शक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति में कमी आ गई, पूँजी और व्यापार प्रवाह में बढ़ातरी होने लगी ऐसे में भारत द्वारा विकसित देशों के साथ –साथ पड़ोसी व क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध सुधरने पर बल दिया गया। इस संदर्भ में लुक इस्ट नीति, गुजराल डॉक्टरीन, वर्तमान में एक्ट ईस्ट नीति हो या भारत का सॉफ्ट पावर वाला नज़रिया इत्यादि जैसे नीतियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। जिसने भारतीय विदेश संबंध के स्वस्थ प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई इस समय के अंतर्राष्ट्रीय मंचों यथा, विश्व व्यापक संगठन ळ.20 ब्रिक्स इत्यादि की भूमिका भी अविस्मरणीय रही।
1991 को आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक विभाजन के वर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। इस विभाजन ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। कहीं न कहीं 70 और 80 के दशक में प्रभावी समाजवाद और साम्यवाद को 1991 में बाज़ारवादी नीतियों में बदल दिया गया। देश एक नई आर्थिक नीति के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर अग्रसर हो रहा था। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने इस नीति को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गोद में बैठना करार दिया था, वहीं उदारीकरण के समर्थक इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे थे।
किसी भी देश की विदेश नीति उसके ऐतिहासिक अनुभव, भू–राजनैतिक स्थिति और उसकी सांस्कृतिक विरासत से अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है, जिन साझे मूल्यों के अनुसार राष्ट्रहित परिभाषित होता है, वह इसी पर निर्भर होते हैं। भारत इसका अपवाद नहीं है। भारत के इतिहास में ईसा के जन्म से कई सौ वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय संबध–संपर्क स्थापित किए जा चुके थे, यह अदान–प्रदान सिर्फ व्यापार तक सीमित कभी नहीं रहा, धर्म और संस्कृति, भाषा और कला, भारतीय 'निर्यात' का एक अभिन्न अंग रहे हैं और न ही यह प्रक्रिया एकतरफा थी।

भारत ने निसंकोच भाव से बाहर की दुनिया से बहुत कुछ ग्रहण भी किया, जो कलांतर में उसकी अपनी पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारीकरण के दौर खासकर 1991 के बाद भारत ने विदेष नीति में कूटनीति का इस्तेमाल का सामंजस्य कर अपनी कुषलता का परिचय दिया।

उदारीकरण के दौर में भारत की विदेष नीति लगातार बदलती और दुरूस्त होती रही है। उसे घरेलू बाध्यताओं तथा वैष्विक संपर्क की संभावनाओं एवं क्षमताओं के अनुसार और भी दुरूस्त किया जाता है। ताकि उसके राष्ट्रीय हितों को तत्कालीन सरकार की धारणा के अनुसार सजाया जा सके। भारत भी अपवाद नहीं है और गुट निरपेक्षता हो या प्रमुख शक्तियों को चुनकर उनके साथ गठबंधन करना हो, राष्ट्रीय हित के मामलों तथा विदेष नीति के मूल उद्देष्य पर आजादी के बाद से अभी तक समूचे राजनीतिक वर्ग का एकसमान मत रहा हे। छोटे या लंबे समय में संभावित लाभों के मुताबिक परिवर्तन किए गए हैं। किन्तु मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के बाद से विदेष नीति में विस्तार की शैली, तरीकों तथा घटकों में नाटकीय परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री ने ''इंडिया फर्स्ट'' को सारगर्भित तरीके से विदेष नीति का प्रमुख उद्देष्य बना दिया और अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस नेताओं को न्योता देकर ''पड़ोस'' को प्राथमिकता देते हुए संपर्क आरंभ किया जिसे कई पर्यवेक्षकों ने उत्कृष्ट और असाधारण लेकिन आवष्यक शुरूआत का नाम दिया। विदेष मंत्री सुषमा स्वराज के अनुसार 170 से अधिक विदेषी प्रतिनिधियों के साथ इस दौरान बातचीत की गई।

विदेष नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती अपने पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विष्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को दुरूस्त करना भी चुनौती होगी क्योंकि वे शक्तियाँ अपना प्रभाव जमाने के लिए होड़ करती रहती हैं। चीन की वैष्विक महत्त्वाकांक्षाएं तो हैं ही, उसके साथ संबंध बनाए रखना बाकी सभी संबंधों की तुलना में सबसे अधिक कठिन रहा हे। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये तथा दरियादिली से खैरात बांटकर भारत के पड़ोस में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेष नीति के उद्देष्यों की राह में बाधक बन सकती है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति उसकी चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए हैं। उनका मुकाबला करना है तो क्षेत्र में हितधारकों को उसी प्रकार का लेकिन और भी आकर्षक तथा वयावहारिक प्रोत्साहन देना होगा, रणनीतिक वैष्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा लगातार किया जा रहा विरोध परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के हमारे प्रयासों को विफल करता रहेगां चीन–पाकिस्तान–रूस के बीच कुछ समय पहले हुई बैठकें तथा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले होने के बावजूद रूस–पाकिस्तान सैन्य अभ्यास इसका उदाहरण हैं।

रूस के साथ भारत के रिष्ते बहुत पुराने और विविधता भरे हैं। लेकिन यह भी सच है कि ''भरोसेमन्द और पुराने दोस्त था'' रूसी–हिन्दी भाई–भाई जैसे भावनात्मक जुमलों से स्थिति पहले की तरह नहीं की जा सकती, लेकिन भारत के साथ सख्त आर्थिक रिष्ते उन्हें ऐसा करने पर मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि खनिजों तथा हीरों के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत अब भी उसके सबसे बड़े बाजाड़ों में शामिल हैं।

चीन के बढ़ते प्रभाव का उत्तर देने के लिए अमेरिकी एषिया प्रषांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत में अधिक स्थान चाहते हैं तो लघु अवधि में यह फायदेमंद हो सकता है। हमें भारत–अमेरिका–जापान त्रिपक्षिय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए यह बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देष्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्थपक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।

अतः आर्थिक वैष्विक व्यवस्था ने भारतीय विदेष नीति को फलने–फूलने का अवसर प्रदान किया है। और वर्त्तमान में भारतीय विदेष नीति नए फलक की ओर अग्रसर हुई। परंतु कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो भारतीय विदेष नीति को प्रभावित कर रही हैं।

उदाहरणस्वरूप आतंकवाद वर्त्तमान विदेष नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौति है।

- पष्चिम एषिया में संघर्ष की स्थिति भी चिंता पैदा करती है
- भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी भारतीय विदेष नीति के लिए चिंता का विषय है।
- हाल ही के दिनों में भारत के साथ चीन का रवैया ठीक नहीं है जो सीमा पर तनाव उत्पन्न किए हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर विवाद, जलवायु परिवर्त्तन की समस्या, प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पद्धा का माहौल, वैष्विक महामारी और अमेरिका और चीन के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाना भी चिंता का विषय है, लेकिन इन सब के बीच भारत को अपनी कुषलता का परिचय देना होगा जैसा की आजादी के बाद से लगातार भारत अपनी कुषल कूटनीति के दम पर दुनिया का ध्यान का अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा है और आगे भी रहेगा।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय विदेष नीति समय के साथ परिवर्तन का गवाह रहा है और वर्तमान में भी वैष्विक व्यवस्था के अनुसार खुद को ढाल रहा है जिसे ऊर्जा, सुरक्षा, जल, अर्थव्यवस्था, व पार्यावरण के संदर्भ में देख सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि विदेष नीति के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा बेहतर कूटनीति अपनाने की जरूरत है।

संदर्भ स्त्रोतः

1. भारत की विदेष नीति–डॉ0 ए0 सी0 सिंहल
2. रंगराजन, चक्रवर्ती 2010, पर्सपेक्टिस ऑफ इंडियन एकोनॉमी : ए कलेक्षन ऑफ एसे, हिंदी एडिषन, राजपाल एण्ड सन्स पब्लिर्षस, न्यू डेल्ही, पेजेज 69 एण्ड 70
3. लाल एस0 एन0 तथा एस0 के लाल 2010 भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विष्लेषण, षिवम पब्लिषर्स, इलाहाबाद, पृ0 सं0–4–6
4. भारद्वाज, रामदेव–भारत और आधुनिक विष्व, म0 प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ0–103
5. कोली, सी0 एम0 प्रमुख देषों की विदेष नीतियाँ, साहित्यागार, पृ0–18
6. कैषमेन, विलियम एच0 द प्राईस ऑफ पीस, न्यूयार्क : लेक्सिंग्टन बुक्स 1993
7. केनेडी पॉल प्रिपेरिंग फॉर द टवन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, इंडियन डिफेन्स एण्ड सिक्योरिटी : इटररीजिनल डाइमेन्सन।